Location	*Computer installed*
Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Madras	80486 based Computer.

राज्यों द्वारा गाडगिल-सूत्र का स्वीकार न किया जाना

2800. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने गाडगिल-सूत्र को स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा गाडगिल-सूत्र पर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) जी, नहीं। कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने फार्मूले में संशोधन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूला निम्नानुसार है:-

I. कुल केन्द्रीय सहायता से, विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अपेक्षित निधियों को अलग रखकर, जैसा अब किया जा रहा है,

II. शेष में से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए संतुलित धनराशि मुहैय्या कराकर, अर्थात्

(क) पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम,
(ख) जनजाति क्षेत्र,
(ग) सीमावर्ती क्षेत्र, और
(घ) पूर्वोत्तर परिषद

III. दस विशेष श्रेणी राज्यों के लिए शेष राशि में से 30 प्रतिशत राशि रखते हुए, और

IV. निम्नलिखित का मानदण्ड के अनुसार पन्द्रह गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच शेष राशि का आवंटन:

मानदण्ड	अधिभार (%)	
(I) जनसंख्या (1971)		60%
(II) प्रतिव्यक्ति आय, जिसमें		25%
(क) विचलन विधि के अनुसार जिनमें केवल वे राज्य आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति एसडीपी राष्ट्रीय औसत से कम है	20%	20%
(ख) "अंतर" विधि के अनुसार सभी 15 राज्य	5%	
(III) कार्य निष्पादन जिसमें		7.5%
(क) पूर्व गाडगिल फार्मूले में यथापरिभाषित "कर प्रयास" के अनुसार	2.5%	
(ख) पूर्व संशोधित फार्मूले में यथापरिभाषित राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार, और	2.5%	
(ग) राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में कार्यनिष्पादन के अनुसार	2.5%	
(IV) विशेष समस्याएं		7.5%

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कतिपय कार्यक्रमों के बारे में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के तहत अनुमोदित फार्मूले में चार लक्ष्य शामिल हैं, जैसे:— (I) जनसंख्या नियंत्रण (II) निरक्षरता उन्मूलन, (III) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, और (IV) भूमि सुधार में सफलता।

उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित की गई धनराशि

2801. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि वित्तीय वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को उसकी वार्षिक योजनाओं के लिए

अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और उक्त अवधि के दौरान वर्षवार वास्तव में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और कितनी धनराशि लौटायी गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): 1990-91 की वार्षिक योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जबकि राज्य सरकार द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार वास्तविक व्यय 3026.21 करोड़ रुपए है। यह कमी मुख्यतः राज्य के अपने संसाधनों की बिगड़ती सिथति के कारण है। 1991-92 वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 3710 करोड़ रु० है जिसे आगे चलकर आदर्श गांवों और सहकारी समिति का इक्विटी बेस जैसी दो स्कीमों को छोड़ दिए जाने के कारण कम करके 3700 करोड़ रुपए कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा अभी व्यय का विवरण दिया जाना है।

निर्यातोन्मुखी धागा मिलों की स्थापना

2802. **श्री अजीत जोगी:**
कुमारी आलिया:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान निर्यातोन्मुखी धागा मिलों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार और अधिक निर्यातोन्मुखी धागा मिलों की स्थापना करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो ये मिलें किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यार्न एककों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के अन्तर्गत यार्न के निर्यात निम्नोक्त अनुसार हुए हैं:—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1988	17.15
1989-90	35.10
1990-91	37.74 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक सरकार की स्थान संबंधी नीति के अध्यधीन उद्यमियों की पसंद के स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं।

Export Target for Garments

2803. SHRI P. UPENDRA:
SHRI KRISHAN LAL SHARMA

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have fixed an export target of Rs. 6380 crores for 1991-92 for garment exports;

(b) whether it is also a fact that export target need for 1991-92 is likely to suffer a short fall;

(c) whether the Apparel Export Promotion Council has expressed any difficulty in reaching the target; and

(d) if so, what actions have been taken by Government to remove these difficulties?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (d) A target of Rs. 6380 crores was fixed for export of garments during 1991-92. The Apparel Export Promotion Council had conveyed to the Government that due to factors like recessionary trends in major importing countries and uncertainties in the erstwhile U.S.S.R., exports of garments in the current year is likely to fall short of the target. Government have released additional quotas in various categories in January, 1992 against flexibilities so as to accelerate exports.

Production and Import of Cotton

2804. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the total production of cotton during the current year, expected consumption, carry over stock, export commitment, import commitment;

(b) what is the domestic price and the landed price of imported cotton;

(c) whether imports of cotton is under D.G.L. or under advance licence scheme; and

(d) if so, what is the total foreign exchange needed for imports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a), (c) and (d) The Cotton Advisory Board (CAB) has estimated the production of cotton